Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 13, Issue No. 2, July-2017, ISSN 2230-7540

राजस्थान में पशुधन एवं डेयरी विकास का भौगोलिक अध्ययन

Dr. Jagphool Meena*

Lecturer, Department of Geography, Government Post-Graduation College, Rajgarh, Alwar, Rajasthan

शोध पत्र सारांश:- *यह शोध पत्र राजस्थान में पशुधन और डेयरी विकास के भौगोलिक अध्ययन से संबंधित है। इस शोध पत्र में हम राजस्थान के पशु संसाधनों और डेयरी विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था में पशुपालन व्यवसाय का विशेष महत्व है। पशुपालन न केवल राजस्थान के लोगों के लिए आजीविका का आधार है, बल्कि यह उनके लिए रोजगार और आय का एक मजबूत और आसान स्रोत भी है। राज्य के रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में, एकमात्र विकल्प बचा है जो भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए पशुपालन व्यवसाय है। जहां एक ओर बारिश के कारण कृषि से जीवन यापन करना मुश्किल है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक रोजगार के अवसर भी नगण्य हैं। ऐसी स्थिति में, ग्रामीण लोगों ने पशुपालन को अपने जीवन के तरीके के रूप में अपनाया है। राज्य की अर्थव्यवस्था पशुपालन व्यवसाय के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारकों से लाभान्वित होती है। वर्तमान में, राज्य में पशुपालन की दृष्टि से पशु-भैंस, भैंस-बकरी, ऊँट, घोड़े, टट्टू और गधे हैं। राजस्थान भेड़ और ऊंट की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है। यद्यपि अधिकांश पशुपालन का काम राज्य के लगभग सभी जिलों में किया जाता है, लेकिन मुख्यतः रेगिस्तान, शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में एक व्यवसाय के रूप में। पशुपालन न केवल ग्रामीण लोगों को स्थायी रोजगार प्रदान करता है, बल्कि पशु आधारित उद्योगों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है।*

शब्द कुंजियाँ - *राजस्थान में पशुधन, राजस्थान में पशुधन विकास, राजस्थान में पशुधन संरचना, पशुधन विकास की समस्याएं और बाधाएँ, पशुधन विकास के उपाय, सुझाव और निष्कर्ष।*

----------X----------

परिचय:-

राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है और कृषि के बाद, पशुपालन को आजीविका कमाने का साधन माना जा सकता है। राजस्थान के पशु धन को विशेष आर्थिक महत्व का माना जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत है जहां पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन है। यह राज्य के शुद्ध घरेलू उत्तराधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान करता है। राजस्थान में देश का 7 प्रतिशत पशुधन है और 25 प्रतिशत भेड़ की आबादी पाई जाती है। भारतीय संदर्भ में पशुधन के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए, कुछ आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

राजस्थान में देश के कुल दूध उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत है।

राज्य के पशुओं का वजन 35 प्रतिशत है।

भारत में भेड़ के मांस में राजस्थान की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है।

ऊन में भारत का राजस्थान का हिस्सा 40þ है

वर्तमान में राज्य में भेड़ों की संख्या भारत की कुल संख्या का लगभग 25þ है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि यह पूरी तरह से कृषि पर निर्भर करती है और कृषि को मानसून का जुआ माना जाता है। इस स्थिति में पशुपालन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

राजस्थान की भौगौलिक स्थिति:

अध्ययन क्षेत्र राजस्थान की स्थिति 23'3' उतरी अक्षांश से 30'12' उतरी अक्षांश (अक्षांशीय विस्तार 7'9') तथा 69'30' पूर्वी देशान्तर से 78'17' पूर्वी देशान्तर (विस्तार 8'47) के मध्य

www.ignited.in

स्थित राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा (231/2' कर्क रेखा अर्थात 23 0 30' उतरी अक्षांश रेखा के उतर में स्थित है। कर्क रेखा राज्य में डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से होती हुई बाँसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती हैं। बाँसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक स्थित शहर है। जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबन्ध में स्थित है।

विस्तार:

उत्तर से दक्षिण तक लम्बाई 826 कि. मी. व विस्तार उत्तर में कोणा गाँव (गंगानगर) से दक्षिण में बोरकुण्ड गाँव (कुशलगढ़, बांसवाड़ा) तक है।

पूर्व से पश्चिम तक चैड़ाई 869 कि. मी. व विस्तार पूर्व में सिलाना गाँव (राजाखेड़ा, धौलपुर) से पश्चिम में कटरा (फतेहगढ़,सम, जैसलमेर) तक है।

उद्देश्य:-

प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्य इस प्रकार हैं।

1. राजस्थान में पशुधन के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन किया गया है।
2. राजस्थान में पशुपालन की विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है।
3. राजस्थान में पशुपालन एवं डेयरी विकास के महत्व को समझाया गया है।
4. राजस्थान में डेयरी विकास हेतु किए गए प्रयासों को स्पष्ट किया गया है।

परिकल्पना:

1. वर्तमान में राजस्थान में पशुधन एवं डेयरी उद्योग में निरन्तर वृद्धि हो रही है।
2. वर्तमान में सरकार द्वारा डेयरी विकास हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

अध्ययन मोडः

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है। प्राथमिक डेटा प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची और व्यक्तिगत संपर्क से संकलित है। माध्यमिक आंकड़ों का संकलन डायरी, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, राजस्थान पशुपालन विभाग, राजस्थान दुग्ध उत्पादन सोसायटी, राजस्थान डेयरी विकास संघ और विभिन्न वेबसाइटों और पुस्तकों के माध्यम से किया गया है। इस अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक है।

राजस्थान में पशुधनः

राजस्थान पशुपालन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। इसमें भारत के कुल पशुधन का लगभग 11.5 प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पशुओं का औसत घनत्व 120 जानवर प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत के औसत घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर 112 जानवर) से अधिक है। 1988 में राज्य में पशुओं की कुल संख्या 409 लाख थी जो 1992 में बढ़कर 492.67 लाख हो गई और 1996 में 568.19 लाख हो गई। पशुओं की बढ़ती संख्या अकाल और सूखे से पीड़ित राजस्थान के लिए वरदान साबित हो रही है। आज, राज्य के शुद्ध घरेलू मूल का लगभग 15 प्रतिशत पशु धन से प्राप्त किया जा रहा है।

www.ignited.in

सम्पूर्ण भारत के संदर्भ में, राजस्थान में ऊन उत्पादन में 45 प्रतिशत, पशु वहन क्षमता में 35 प्रतिशत और दुग्ध उत्पादन में 10 प्रतिशत का योगदान है।

वर्तमान में, राज्य में पशुपालन की दृष्टि से पशु-भैंस, भैंस-बकरी, ऊँट, घोड़े, टट्टू और गधे हैं। राजस्थान भेड़ और ऊंट की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पर है। यद्यपि अधिकांश पशुपालन का काम राज्य के लगभग सभी जिलों में किया जाता है, लेकिन मुख्यतः रेगिस्तान, शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में एक व्यवसाय के रूप में। पशुपालन न केवल ग्रामीण लोगों को स्थायी रोजगार प्रदान करता है, बल्कि पशु आधारित उद्योगों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। अकाल और सूखे की स्थिति में, पशुपालन ही एकमात्र सहारा है। यह व्यवसाय पौष्टिक भोजन - घी, मक्खन, छाछ, दही, आदि के साथ-साथ डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़े के चारे आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, बड़े पैमाने पर मांस उत्पादन के साथ, चमड़े और हड्डियों को भी प्राप्त किया जाता है, जो विदेशों से निर्यात किया जाता है।

राजस्थान में पशुधन विकासः

अर्थव्यवस्था में व्यापार की उपयोगिता के कारण, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उचित प्रयास किए गए हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में पशुधन विकास पर व्यय की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। यद्यपि यह राज्य पहली योजना अवधि में अपनी एकीकरण समस्याओं से जूझ रहा था और कृषि विकास के साथ पशुधन विकास व्यय शामिल था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में पशुधन विकास पर 1.25 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। जो सातवीं योजना में 37.6 करोड़ रुपये और आठवीं योजना में 87.3 करोड़ रुपये हो गया। नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्य में पशुधन विकास के लिए लगभग 109.34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में पशुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, उनकी चिकित्सा सुविधाओं का भी लगातार विस्तार किया जा रहा है। राज्य के पशु चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 1951 में केवल 147 थी, जो 1984-85 में बढ़कर 1106 और 1993-94 में 1457 हो गई। इनके साथ-साथ 55 मोबाइल अस्पताल, 8 जिला पशु अस्पताल और 13 रिंडरपेस्ट कंट्रोल सेंटर भी चलाए जा रहे हैं।

विभिन्न जानवरों की नस्ल सुधार, रोग नियंत्रण और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता के संदर्भ में भी कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। जहां बकरी किसानों की मदद के लिए स्विट्जरलैंड सरकार की मदद से अजमेर, भीलवाड़ा और सिरोही जिलों में बकरी विकास और चारे की उत्पादन योजना शुरू की गई है, वहीं दूसरी ओर, ऊँट की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए कई सार नियंत्रण इकाइयों की स्थापना की गई। है। इसी तरह, सुअर के कारोबार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अलवर और भरतपुर जिलों में सुअर विकास फार्म खोला गया है। इसी तरह, गायों की नस्ल में सुधार और संरक्षण के उद्देश्य से लगभग 280 गौशालाएँ चलाई जा रही हैं। कुछ गौशालाओं को केंद्र सरकार से वित्तीय अनुदान मिलता है और अधिकांश अन्य स्कूलों को राजस्थान गौ सेवा संघ के संरक्षण और निर्देशन में चलाया जा रहा है। गायों और सांडों की नस्ल सुधारने के लिए 58 गौ-प्रजनन शाखाएँ काम कर रही हैं।

राजस्थान में पशुपालन व्यवसाय को उन्नत करके ग्रामीण विकास को गति देने के लिए ग्रामधार योजना भी शुरू की गई है। जिसके तहत उन्नत नस्ल के पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रजनन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। दूसरी ओर, संतुलित पशु चारा और चारा उत्पादन प्रणाली विकसित करने के साथ-साथ पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा, ग्रामीणों को पशुपालन के वैज्ञानिक तरीकों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उचित विपणन व्यवस्था करने

www.ignited.in

के साथ-साथ कृत्रिम गर्भाधान और चारा विकास केंद्रों के विस्तार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

गोपाल योजना भी 1989-90 से राज्य में पशुधन मालिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को कृत्रिम गर्भाधान, निवारक दवाओं का उपयोग, बाँझपन की रोकथाम, संतुलित आहार, पशुओं की आधुनिक देखभाल आदि के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक यह योजना 45 पंचायत समितियों में चलाई गई है। दक्षिणपूर्वी राजस्थान के 12 जिलों में। राजस्थान में पशुधन का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से देखा जा सकता है।

(1) राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदानः

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का लगभग 9þ हिस्सा है।

(2) गरीबी उन्मूलनः

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में पशुपालन के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में, दुधारू पशुओं को देकर गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन इसके लिए चारे और पानी की उचित व्यवस्था करनी पड़ती है और लाभार्थी परिवारों को बिक्री की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

(3) नौकरी सृजनः

पशुपालन से उच्च आय और रोजगार की संभावनाएं हैं। पशुओं की खपत बढ़ाकर आय बढ़ाई जा सकती है। राज्य के शुष्क और अर्ध-शुष्क भागों में, कुछ परिवार (विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर) बहुत सारे पशुपालन करते हैं और वंश परंपरा में उनका काम जारी रहा है। इन क्षेत्रों में, पशुपालन से शुद्ध घरेलू उत्थान का एक उच्च अनुपात उत्पन्न होता है। इसलिए रेगिस्तान की अर्थव्यवस्था मूल रूप से पशु आधारित है।

(4) डेयरी विकासः

पशुधन की मदद से, ग्रामीण दूध उत्पादन शहरी उपभोक्ताओं के साथ जुड़ा हुआ है, शहरी क्षेत्र की दूध की आवश्यकता और ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका की आपूर्ति है। राजस्थान देश के कुल दूध उत्पादन का 10 प्रतिशत उत्पादन करता है। राज्य ने 1989-90 में 42 लाख टन दूध का उत्पादन किया, जो 2003-04 में बढ़कर 80.5 लाख टन हो गया।

(5) परिवहन का तरीकाः

राजस्थान में पशुधन की विशाल क्षमता है। बैल, भैंस, ऊंट, गधे, खच्चर आदि का उपयोग कृषि और कई परियोजनाओं में भार उठाने और ले जाने के लिए किया जाता है। देश की कुल वहन क्षमता का 35 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान के पशुओं द्वारा वहन किया जाता है। देश में कुल 300 मिलियन टन माल रेल और ट्रकों द्वारा ले जाया जाता है, जबकि 70 मिलियन टन माल अभी भी बैलगाड़ियों द्वारा ले जाया जाता है।

(6) खाद की प्राप्तिः

पशुपालन के माध्यम से कृषि के लिए खाद भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में, पशु के गोबर से बना "वर्मीकम्पोस्ट" भोजन उच्च परिसंचरण में है।

राजस्थान में पशुधन की संरचनाः -

राज्य में विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। जिनकी संख्या नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।

2015 में विभिन्न प्रकार के जानवरों की संख्या

गाय या गाय 1.49 करोड़

भैंस जाति का 1.44 लाख

भेड़ पालकों की 1.10 करोड़ रुपये

1.98 करोड़ की बकरी-जाति

ऊंट, घोड़े, गधे, सूअर आदि 0.20 करोड़ या 20 लाख

इस प्रकार संख्या के संदर्भ में, पशु और भेड़ और बकरी जानवरों में प्रमुख हैं। राजस्थान में उपलब्ध विभिन्न जानवरों जैसे गाय, बकरी, भेड़ आदि का निम्नलिखित विवरण।

1. राजस्थान में गायः

गाय पशुपालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इसकी निम्न नस्लें राजस्थान में पाई जाती हैं। गौ-वंश के पास कुल पशु धन का 22.8 प्रतिशत है।

www.ignited.in

नागौरीः

इसका प्रमुख क्षेत्र नागौर का "सुहालक" क्षेत्र है। इस प्रकार का बैल ज्यादातर जोधपुर, नागौर और नागौर से सटे पड़ोसी जिलों में पाया जाता है। इस नस्ल की गायें कम दूध देती हैं।

छूटः

बाड़मेर, सिरोही और जालौर जिले राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। इस नस्ल की गायें प्रतिदिन 5 से 10 लीटर दूध देती हैं। इस नस्ल के बैल भी अच्छे वजन वाहक हैं। इसलिए, यही कारण है कि इस नस्ल की गाय-संतान को "दोतरफा दौड़" कहा जाता है।

थारपारकरः

इसका उद्गम स्थल मैलानी (बाड़मेर) है। यह गाय अत्यधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है, इसे स्थानीय रूप से "मैलानी नस्ल" के रूप में जाना जाता है।

राठीः

यह राजस्थान के पश्चिमोत्तर भागों में श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में पाया जाता है।

इस नस्ल की गायें अत्यधिक दूध के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन इस नस्ल के बैलों में कम असर वाली क्षमता होती है।

गिरनाः

यह गिर बान, सौराष्ट्र, गुजरात में रहने वाला एक जानवर है। ये जानवर दक्षिण-पूर्वी भाग (अजमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा आदि) में सबसे अधिक पाए जाते हैं।

2. भेड़ः

देश के कुल झुंडों का लगभग 25 प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है। राज्य के लगभग 2 लाख परिवार पशुपालन के काम से जुड़े हैं।

भेड़ की मुख्य नस्लें इस प्रकार हैं।

1. जैसलमेरीः

यह जैसलमेर में पाया जाता है।

2. नालीः

यह हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर और झुंझुनू जिलों में पाया जाता है। यह अधिक ऊन के लिए प्रसिद्ध है।

3. मालपुरीः

इसे "देशी नस्ल" भी कहा जाता है। यह जयपुर, दौसा, टोंक, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में पाया जाता है।

4. मगराः

यह प्रति वर्ष औसतन 2 किलो ऊन देता है। इस नस्ल की भेड़ें ज्यादातर जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, नागौर आदि में पाई जाती हैं।

5. पुगलः

बीकानेर की तहसील "पुगल" के रूप में उनके उद्गम स्थल के कारण, यह पुगल बन गया।

6. मारवाड़ी नस्लः

राजस्थान में कुल भेड़ों की मारवाड़ी नस्ल (लगभग 45 प्रतिशत) है। यह राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर, पाली, दौसा, जयपुर आदि जिलों में सर्वाधिक पाया जाता है।

7. चोकला या शेखावाटीः

इसे भारत का मेरिनो भी कहा जाता है। यह ऊन देने वाली नस्ल का सबसे अच्छा प्रकार है। यह हर साल 1 से 1.5 किलो ऊन देता है।

www.ignited.in

8. सोनाडीः

राजस्थान में बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिले पाए जाते हैं। जब यह भेड़ जमीन पर घास चरती है, तो इसके कान जमीन को छूते हैं।

समस्याएं और बाधाएँ

पशुपालन व्यवसाय के विकास और विस्तार के लिए इन उपायों के बावजूद, कुछ बुनियादी और संरचनात्मक समस्याओं के कारण, पशुधन बेहतर रूप से विकसित नहीं हो रहा है। पशुपालकों के निरक्षर होने के कारण उन्हें आधुनिक तरीकों से प्रशिक्षित करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालक अपनी गरीबी के कारण न तो पशुओं को पौष्टिक आहार दे पा रहे हैं और न ही उनकी बीमारियों का निदान कर पा रहे हैं। कई बार समय पर इलाज न मिलने के कारण सैकड़ों पशुओं के एक साथ मरने से मवेशी गंभीर आर्थिक संकट में फंस जाते हैं।

अधिकांश झुंड कमजोर और खराब नस्ल के जानवरों के मालिक हैं। इसके अलावा, कृषि ज्यादातर लोगों की आजीविका का आधार होने के कारण, चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि नहीं बची है। परिणामस्वरूप, जानवरों को सूखे पत्तों और डंठल आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। कृषि उत्पादन पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करता है, लेकिन अपर्याप्त वर्षा के कारण हर तीन से चार साल बाद पूर्ण या आंशिक अकाल की छाया होती है। जिसके कारण अधिकांश जानवर अकाल से प्रभावित हैं। और झुंड मुसीबत में पड़ जाते हैं। ज्यादातर पशुपालक पारंपरिक और रूढ़िवादी तरीकों से ही पशुपालन करते हैं। इन सभी कारणों से, आज भी पशुपालन के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाया है।

पशुधन विकास की समस्याएं

1. मानसून की अनिश्चितताः

राजस्थान में लगातार सूखे की समस्या है। इस कारण पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है।

2. योजना और समन्वय का अभावः

सरकार अभी तक इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी योजना नहीं बना पाई है। और समन्वय की कमी देखी गई है।

3. पशु स्वास्थ्य योजनाः

अक्सर देखा गया है कि किसी बीमारी के कारण सभी जानवर चपेट में आ जाते हैं। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए नियोजन और सुविधाओं का अभाव देखा गया है।

4. पशु आधारित उद्योगों का अभावः

राजस्थान में ऊन, दूध और चमड़ा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन राजस्थान में इन पर आधारित उद्योगों की कमी के कारण, राज्य को दूध, चमड़ा अन्य राज्यों या अन्य राज्यों को निर्यात करने का पर्याप्त लाभ नहीं मिलता है।

पशुधन विकास के लिए समाधानः

1. "गोपाल" कार्यक्रमः -

कार्यक्रम 1990‑91 में शुरू किया गया था। यह एनजीओ या गाँव शिक्षित युवाओं (गोपाल) को उचित प्रशिक्षण देने और उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें, विदेशी नस्ल के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग के लिए कृत्रिम गर्भाधान की विधि में गोपाल को प्रशिक्षित किया जाता है। किसी क्षेत्र की बेकार सीडल पूरी तरह से डाली जाती हैं। किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है कि वे अपने जानवरों को स्टाल पर कैसे खिलाएं और हमेशा बाहर चरने की विधि पर निर्भर न हों।

2. भेड़ प्रजनन कार्यक्रमः

राज्य में ऊन और मांस के उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए भेड़ प्रजनन में सुधार के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। क्रॉस-ब्रीडिंग कार्यक्रम नाली, चोकला, सोनाडी और मालपुरा नस्लों पर लागू किया गया है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान के जरिए भेड़ों की नस्ल में सुधार किया जाता है। इसके अलावा, चयनित प्रजनन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

3. विपणन प्रणालीः -

एक तरफ पशुओं की खरीद और बिक्री के लिए पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, ताकि पशुपालकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। दूसरी ओर, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को दुग्ध बिचैलियों के बिना उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंच बनाने के लिए स्थापित किया गया है। राज्य में पशु मेले ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और पंचायत समितियों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान में राज्य में 50 पशु मेले हैं, जिनमें से 10 मेले राज्य स्तर के प्रसिद्ध पशु मेलों, पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

4. पशु चिकित्साः

पशु रोगों से बचाव और रोकथाम के लिए राज्य में नए अस्पताल खोले गए हैं। जहां 1951 में 147 अस्पताल थे। 2001-02 में राज्य में 12 पशु चिकित्सालय, 22 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 1386 पशु चिकित्सालय, 285 पशु औषधालय और 1720 उप-केंद्र कार्यरत हैं। इसके अलावा, राज्य में 34 जिला रोग प्रयोगशालाएँ काम कर रही हैं। पशुपालकों को उनके घर पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए उपखंड स्तर पर 8 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई स्थापित करने की योजना है।

5. एकीकृत पशु विकास कार्यक्रमः

8 वीं योजना की शुरुआत में, इसे जयपुर और बीकानेरसम्बाग में शुरू किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के कोटा, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर संभाग के 21 जिलों में लागू है जहाँ 749 उप-केंद्र स्थापित किए गए हैं।

पशु स्वास्थ्य के अलावा, इस योजना में कृत्रिम गर्भाधान, अपशिष्ट जानवरों की नसबंदी और बेहतर किस्म के चारे के बीज का वितरण शामिल है।

6. पशुपालन और अनुसंधानः

राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बीकानेर और जयपुर में दो पशु चिकित्सा कॉलेज स्थापित किए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीकानेर और सूरतगढ़ में भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। जोधपुर में, एक भेड़ और भेड़ प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया है। विश्व बैंक की मदद से, पशु चिकित्सकों और अधिकारियों ने जामडोली में राजस्थान पशु धन प्रबंधन संस्थान के विशेष तकनीकी प्रशिक्षण के लिए निर्माण कार्य किया है।

7. डेयरी विकास पर प्रौद्योगिकी मिशनः -

भारत सरकार ने डेयरी विकास पर एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. उत्पादकता बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाकर ग्रामीण रोजगार और आय बढ़ाएं

2. दूध और दूध उत्पादों की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए।

8. राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रमः -

डेयरी या दूध विकास नीति के तहत, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन अमूल के नमूने पर राष्ट्रीय डेयरी विकास के सहयोग से राज्य में एक डेयरी कार्यक्रम चला रहा है। डेयरी फेडरेशन उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने में लगी हुई है। यह पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार, पशु आहार की सुविधाओं और दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए भी प्रयास कर रहा है। वर्तमान में, दूध का संग्रह 16 जिला डेयरी संघों द्वारा किया जा रहा है, जिनकी क्षमता 9 लाख लीटर से बढ़ाकर 14.30 लाख लीटर प्रतिदिन कर दी गई है। राज्य के सभी 30 जिलों में गहन डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्य में 16 दुग्ध उत्पादक संघों का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। 2006-07 में, दिसंबर 2006 तक डेयरी फेडरेशन का औसत दूध संग्रह 13.49 लाख किलोग्राम प्रति दिन था और इसकी दूध की बिक्री औसतन 12.01 लाख लीटर प्रति दिन थी।

मार्च 2006 के अंत में, दुग्ध उत्पादक प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 8874 हो गई और जिला दुग्ध संघों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। सहकारी समितियों के विकास के परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादकों को बहुत लाभ हुआ। विपणन के साथ दूध उत्पादन को जोड़ने से दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य और मध्यम वर्ग के शोषण से मुक्ति मिल सकेगी। डेयरी फेडरेशन के अंतर्गत 4 पशु चारा संयंत्र कार्यरत हैं। जिसमें पशु आहार का उत्पादन और विपणन किया जाता है।

सुझावः

राज्य के जानवरों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, एक तरफ पशुपालकों को शिक्षित करना और उन्हें आधुनिक तरीकों से प्रशिक्षित करना आवश्यक है, दूसरी ओर, सभी क्षेत्रों में पशुओं की नस्ल सुधार योजनाओं को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है

www.ignited.in

अधिक प्रभावशाली रुप से। सरकार को पशुओं की संक्रामक बीमारियों को जल्द से जल्द रोकने के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। पशुपालकों को जागरूक कर पशु संवर्धन कार्यक्रमों और योजनाओं को सफल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, उन्हें सरल और कम ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण मिलना चाहिए और अकाल और सूखे की स्थिति में पशुपालकों को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। पूरे वर्ष उपलब्ध होने वाले चारे को विकसित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पशु बीमा योजना को राज्य के सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचारित और प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

सभी जिलों में, दूध की बिक्री की तरह, जानवरों से प्राप्त अन्य पदार्थों की बिक्री के लिए सहकारी समितियों की भी स्थापना की जानी चाहिए। अनुत्पादक जानवरों की संख्या के आधार पर, पशुपालकों को सरकार से वित्तीय और चारा अनुदान मिलना चाहिए। पशुपालन के प्रति आजीविका कमाने के बजाय, एक पेशेवर दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि पशुपालन व्यवसाय को पूर्ण व्यवसाय बनाया जा सके। राज्य के पशुपालन व्यवसाय को समृद्ध करने के लिए, यह भी आवश्यक है कि यहां पशु आधारित उद्योग विकसित किए जाएं। ऐसा करने से न केवल राज्य के पशुपालकों की आय बढ़ेगी, बल्कि राज्य के औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्षः

राजस्थान में पशुपालन और डेयरी के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार में वृद्धि हुई है। छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक रूप से लाभ हुआ है। समाज के गरीब तबके को फायदा हुआ है, मानव आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी है तथा बायो-गैस के द्वारा ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्त्रोत का विकास भी हुआ है। शहरी क्षेत्रों में दूध व दूध से बने पदार्थों से मांग की पूर्ति करने में मदद मिली है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. राजस्थान का भूगोल, प्रोफेसर एच एस शर्मा, पंचशील प्रकाशन, जयपुर
2. राजस्थान की अर्थव्यवस्था, प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण नाथूराम, कॉलेज बुक हॉउस, जयपुर
3. राजस्थान का भूगोल, डॉ हरिमोहन सक्सेना, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
4. राजस्थान सुजस, त्रिमासिक पत्रिका, राजस्थान सरकार, जयपुर
5. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड (RIICO)
6. सूचना एवं जन संचार प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
7. राजस्थान डेयरी विकास संघ, जयपुर।
8. पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार।
9. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान - राजस्थान अध्ययन

Corresponding Author

Dr. Jagphool Meena*

Lecturer, Department of Geography, Government Post-Graduation College, Rajgarh, Alwar, Rajasthan